छह साल में शहरों के विकास पर सात गुना अधिक खर्च हुआ धन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय अवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि जिस प्रकार से शहरी आबादी में वृद्धि हो रही है, उसकी तुलना में शहरों के विकास पर फोकस किसी सरकार का नहीं था। लेकिन 2014 के बाद पहली बार मोदी सरकार ने शहरों के विकास पर फोकस किया। आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि शहरों के विकास पर बीते छह साल में करीब सात गुना अधिक धन खर्च किया गया है।

केंद्रीय अवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश के नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री सोमवार को मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। पर कांग्रेस सरकार ने इन 10 सालों में शहरों के विकास

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री का आरोप, कांग्रेस का नहीं था शहरों पर फोकस

पर मात्र 1.57 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। वहीं, 2014 के बाद मोदी सरकार ने सिर्फ 6 साल में शहरों के विकास पर 11.83 लाख करोड़ खर्च किए। इसमें खास तौर पर साफ-सफाई, अवस्थापना विकास व पर्यावरण सुधार, पेयजल और मलिन बस्तियों के विकास आदि पर फोकस किया गया। उन्होंने दावा किया कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, पीएम स्वनिधि समेत अन्य योजनाओं को सिर्फ एक योजना की तरह नहीं चलाया गया बल्कि इसे एक जनांदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इससे शहरी इलाकों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा।

केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी बेहतर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहरों के विकास से संबंधित सभी केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी का रेकॉर्ड अन्य प्रदेशों का तुलना में बेहतर रहा है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें लखनऊ और कानपुर का रेकॉर्ड दिल्ली, चेन्नई व हैदराबाद से भी अच्छा है।

पुरी ने बताया कि यूपी में अभी कुल 82 किमी. रूट पर मेट्रो रेल सेवा का संचालन हो रहा है। इसमें से 62 किमी. पर संचालन योगी सरकार में शुरू हुआ। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और आगरा में करीब 131 किमी. पर मेट्रो और 82 किमी. रूट पर रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का काम चल रहा है। गोरखपुर में लाइट मेट्रो चलाने का प्रस्ताव केंद्र में विचाराधीन है। यदि कुछ और शहरों में लाइट मेट्रो चलाने का प्रस्ताव आता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा।

गोरखपुर में लाइट मेट्रो का प्रस्ताव

पेट्रोलियम पदार्थ पर जीएसटी को लेकर राज्य असहमत

पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत पर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री पुरी ने कहा कि इसको जीएसटी में शामिल करने को लेकर राज्य सहमत नहीं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम होंगे। इस बारे में सरकार इसका रास्ता निकालने पर विचार कर रही है।